भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5254

दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व

5254. **श्री देवुसिंह चौहान:**

श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को किस प्रकार आकर्षित करने की योजना बना रही है;

(ख) नीति आयोग सम्मेलन में हुई चर्चा के अनुसार अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है;

(ग) सरकार भारत की आर्थिक एवं राजनयिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों क्षेत्रों के साथ रणनीतिक साझेदारी को किस प्रकार संतुलित करने की योजना बना रही है; और

(घ) क्या कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किसी कानूनी सुधार पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा में देश के नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा पहल की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. वर्ष 2030 तक भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 50% गैर-जीवाश्म आधारित विद्युत क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत इस प्रतिबद्धता को प्राप्त करने वाले प्रथम कुछ देशों में से एक है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है।

2. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) का शुभारम्भ करके नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने में वैश्विक नेतृत्व दिखाया है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा के परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए आईएसए ने 123 सदस्य देशों के गठबंधन तक विस्तार किया है।

3. भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की भी शुरूआत की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन करना है ताकि भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाया जा सके।

4. भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। सरकार ने विदेशी निवेश वाले क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की निकासी को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर को भी बढ़ावा दिया है।

(ख): सम्मेलन में, अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के अधिक निवेश की आवश्यकता को मान्यता दी गई, लेकिन नीति आयोग ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना प्रस्तावित नहीं की।

(ग): सरकार ने भारत की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैश्विक दक्षिण और उत्तर के साथ साझेदारी को संतुलित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन और गरीबी जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए विकास सहयोग के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़कर कार्य करना। साथ ही, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी साझाकरण और नीतिगत शासन पर वैश्विक उत्तर के साथ भागीदारी करना। भारत के पास वैश्विक दक्षिण देशों के साथ एक मजबूत विकास साझेदारी कार्यक्रम है जिसके तहत सरकार ऋण, अनुदान के साथ-साथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करती है।

2. भारत यह दर्शाने में अग्रणी रहा है कि आर्थिक विकास जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप तरीका अपनाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। भारत वैश्विक दक्षिण के सरोकारों का भी समर्थन कर रहा है, जैसा कि सीओपी 29 में देखा गया है। हाल के सीओपी 29 में, भारत ने इस बात पर ध्यानाकर्षित किया कि वैश्विक दक्षिण को

जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने में वैश्विक उत्तर को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

3. भारत ने सीओपी 26 में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट (लाइफ) लॉन्च किया, जिसका मानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरागत जीवनशैली स्वाभाविक रूप से संधारणीय है। यह वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को प्रसारित करना चाहता है।

4. भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करने की पहल की। इसके अलावा, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए), और आपदा प्रतिरोध अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) सहित कई पहलों का नेतृत्व किया है।

(घ): सम्मेलन के दौरान, आमतौर पर यह स्वीकार किया गया कि निवेश को आकर्षित करने और व्यापार करने में सुगमता के लिए कानूनी सुधार महत्वपूर्ण है। हालांकि, नीति आयोग द्वारा कोई विशिष्ट सुधार करना निर्धारित या प्रस्तावित नहीं है।

*****